





"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिपा

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 1 मई 2024 बुधवार

## सम्पादकीय

### मजदूरों की दशा दिशा

एक दौर था जब मानव प्रकृति का था और प्रकृति मानव की। न कोई शोषक न कोई शोषित। कालचक्र के साथ परिस्थितियों में बदलाव आना शुरू हुआ। मनुष्य जहाँ प्रकृति के वश में था अब वह प्रकृति के साथ संघर्ष में उतारू हो गया। निजी संपत्ति का मालिक बनने, पूंजी व उत्पाद को जमा करना उसकी नियति बनती गई। निजी संपत्ति ने मजदूर वर्ग को जन्म दिया और यहाँ से शुरू हुआ शोषण का अंतहीन दौर। इसी शोषण प्रक्रिया ने दास प्रथा को जन्म दिया। कमजोर वर्ग बलशाली शासक के अत्याचारों का न सिर्फ निशाना बना बल्कि भीड़-दर-भीड़ गुलामी करने के लिए भी उसे लाचार बना दिया गया।

19 वीं सदी में कल कारखानों के आविष्कार और उत्पादन प्रक्रिया को बल मिला। मालिकों द्वारा कारखानों में मजदूरों से 16 से 18 घंटे काम करवाया जाता था और बदले में मजदूरों के श्रम का नाम मात्र पारिश्रमिक दिया जाता था ताकि वे जिंदा रह सकें। शोषण की इस चक्की में दिन-रात मजदूर पिंसने लगा और एक दिन मालिकों के इन अत्याचारों व शोषण के खिलाफ पहली बार अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूर संघ का निर्माण हुआ। जिसके अंतर्गत मजदूरों द्वारा काम के 8 घंटे तय करने का अल्टीमेटम कारखाना मालिक को दिया गया।

मांगें नहीं मानने की एवज में मजदूरों ने, शिकागो के हे मार्केट चौक में एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जहाँ मालिक के इशारे पर पुलिस द्वारा, शान्तिपूर्ण सभा पर, गोलीयाँ बरसाई गईं और इस आंदोलन में 6 मजदूरों को अपनी शाहादत देनी पड़ी। 1 मई 1886 को मजदूरों ने अपने हक की लड़ाई शुरू की थी। एक माँ की गोदी में दुधभरे मासूम की मौत हो गई। माँ ने खून से सनी अपने बेटे की कमीज को बड़े से बाँस के बाँध कर लाल झंडे के रूप में ऊँचा करके मजदूरों का आह्वान किया।

स्वामिकावै है कि इस आंदोलन की चिंगारी दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल गई और पेरिस के मजदूरों ने शिकागो शहर में शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। 1989 में पेरिस में मजदूरों की बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दुनिया के हर देशों में मजदूरों ने अपनी एकता के बल पर शोषक निजाम के खिलाफ कारखाने आंदोलन शुरू कर दिए। श्रम का वाजिव दाम और काम के 8 घंटे निश्चित करने की मांग ने पूरे विश्व को हिला दिया। "दुनिया के मजदूरों एक हो" नारे का जन्म 1 मई 1886 का शिकागो आंदोलन ही है।

इसी संदर्भ में भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास में मजदूरों द्वारा मई दिवस मनाया गया। इस आंदोलन की शुरुआत 'लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान' ने की। वर्तमान में भी पूरी दुनिया के पैमाने पर मजदूर, समाजों के माध्यम से अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं, जुलूस निकालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा मध्य आयोजन किए जाते हैं।

मजदूरों की एकता और संघर्ष के बल पर किए गए आंदोलनों ने सरकारों को झुकाने में कामयाबी हासिल की है। कानूनों में यह मान्यता दी गई कि प्रत्येक मजदूर को बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अपनी श्रम शक्ति का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है। मजदूर, श्रमिक को जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर कार्य का चुनाव करने की पूर्ण आजादी है। श्रमिक को बंधुआ या गुलाम बनाकर काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

दो वर्ग जिनमें एक पूँजीपति वर्ग है जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा धन का शोषण कर अपनी पूंजी का इजाफा करना है, वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग जो मेहनत करने के बाद भी अभाव की जिन्दगी जीने पर मजबूर है। अमरीकी गरीबी की खाई लगातार गहरा होती जा रही है और आज भी मजदूर अपने हक के लिए लड़ाई संघर्ष में हैं। खेतों और कारखानों में काम के दौरान जिन मजदूरों की मौत हो जाती है, उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता है।

किसी भी देश की तरक्की उस देश के मजदूरों, किसानों, कारीगरों पर निर्भर होती है, वर्तमान में भारत के मजदूरों की दशा में कोई खास अंतर नहीं आया है। शोषण की प्रक्रिया जारी है। उदाहरण के तौर पर मजदूरों के शोषण को और तेज कर दिया है। नई तकनीक ने बेरोजगारों की भीड़ खड़ी कर दी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मजदूरों के श्रम का शोषण किया जा रहा है। पड़े-लिपटे घात्र जिड़ों या इन्फ्रामा लेकर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 10 से 12 घंटे काम करने पर मजदूर हो रहे हैं। लड़ाई लंबी है पर लड़ना तो होगा ही। मजदूर और मजदूर के अंतर को पाटना होगा। अभी देश समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। अगर किसी जगह पर मजदूरों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो इसे सार्वजनिक करना और अनीति के खिलाफ आवाज उठाना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज बनता है।

# यूपी में बदलती राजनीति और चुनाव

—योगेन्द्र यादव—

इस चुनाव में भाजपा की सफलता उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश में देश की सबसे अधिक 80 संसदीय सीटें हैं और भाजपा के अधिकतम सांसद यहीं से आते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यहां से भाजपा ने 71 और 62 सीटों पर अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर देश की सत्ता पर दावेदारी ठोकी थी। उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिन्दी पट्टी में यही एकमात्र प्रदेश है जहां भाजपा और कहीं भी हुई घाटे की भरपाई कर सकती है। बाकी सब हिन्दी प्रदेशों में तो भाजपा लगभग सभी सीटें जीती थी, इसलिए और ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। पिछले एक-दो महीने से एक सवे के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि इस बार तो भाजपा अपने पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ देगी, 70 पर जाएं और यहां तक कि पूरे 80 के दावे किए जा रहे हैं।

इन दावों की जांच करने के लिए हम कुछ साधियों में दो चरणों में उत्तर प्रदेश के 15 संसदीय क्षेत्रों की यात्रा की। पहले चरण में अंग्रेजों के पहले एसेल में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुक्तनगर, कैराना और सहायपुर तथा अंग्रेज के तीसरे एसेल में बाराबंकी, मोहनलालगंज, उन्नाव, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी तक यात्रा की जाक छानी। इस पूरे यात्रा में हमने देखा है यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा उलटफेर होने जा रहा है।

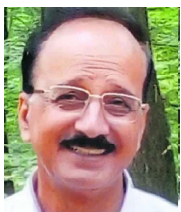


जिनका मेन की थाक लेने के लिए हमने कोई तयारी की सर्वे या किसी खुफिया तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। हमने जो किया उसे चाहे तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इलाके में खुद चौक भी कर सकते हैं। हम 5-6 व्यक्ति एक साथ गाड़ी में बैठकर सुबह से देर शाम तक गांव-दोहात में घूमते थे और साथ-साथ हमें पता चलता था कि क्या बात है, पिछले बार कहा था, और इस बार कैसे जाएगा। चुनाव के मिजाज और लोगों के अपने रुझान के बारे में बातचीत करते तक इतना थका जरूर रहते थे कि सड़क के किनारे या गांव के कुछ बड़े परिवारों से बात करने की बजाय सभी जाति समुदाय के लोगों से बात करें, नेओया या पत्रकारों से पूछने की बजाय एक साधारण वोटर से बातचीत करें। हमारे इतने सफर से उत्तर प्रदेश का बुलेटखंड बंग, पूर्णचल के बिहार से

सटे जिले और प्रदेश के बड़े शहर अछूते रहे। हमारी बातचीत महिलाओं की तुलना में पुरुषों से अधिक हुई है। यह हमारे निष्कर्ष की सीमा हो सकती है। प्रदेश के सैकड़ों साधारण वोटरों से हुई इस बातचीत के आधार पर एक बात तो बिस्वुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में परिवर्तन की हवा है। यानी कि 2019 की अपनी स्थिति में सुधार करने की बजाय भाजपा यहां तक भी पहुंचती दिखाई नहीं देती। अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि भाजपा के वोट में गिरावट किन्ती है और उसका कारण पर किन्ता अगर होगा। यह भी पूरी तरह साफ नहीं था कि यह परिवर्तन की बजाय इस बार क्यों चल रही है। इन बातों को समझने के लिए अभी कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा।

परिवर्तन की इस हवा को अभी से भाजपा के खिलाफ आँधी नहीं उभर आने जन्मता में भाजपा के कहा जा सकता। प्रथममंत्री मोदी की अंधमति बहुत कम हो गई है, लेकिन एक सामान्य वोटर में उनके प्रति अभी गुस्सा नहीं है। एक बड़ी छुपी-छुपी निराशा है, उससे भी ज्यादा धकान है। अब मोदी का नाम लेते भर से बाकी सब मुद्दों पर चर्चा रुक नहीं जाती। एक साधारण वोटर कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई 5 किलो राशन की योजना का श्रेय मोदी जी को देता है, लेकिन इस बात सिर्फ उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के गांवों में मोदी की तुलना में योगी ज्यादा लोकप्रिय हैं, उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। साथ ही योगी के समर्थक यह आशंका भी जाहिर करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और यशुधर राजे सिंघिया की तरह उरफा का राजा जा सकता है। कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव योगी जी का नहीं है।

## मुक्त व्यापार को लेकर दबाव का बढ़ता सिलसिला



—देविंदर शर्मा—

मुक्त व्यापार कभी भी निषेध नहीं रहा। पहले की फेर एंड लवली क्रिम, जिसे अब 'ग्लो एंड लवली' नाम दिया गया है, की तरह फ्री ट्रेड दुनियाभर के बड़े कारोबारों को आसानी से आकर्षित कर सकता है ताकि विकास साउथ के देशों यानी गरीब व निकलसशील देशों को इक्की विशाल आर्थिक क्षमता पर विश्वास हो सके। विवादस्पद फेर एंड लवली क्रिम ने भी लूचो को कथित गौरा करने वाले कॉन्सिडर उच्चारण के साथ ऐसा ही किया। 'गोरे' को सुंदर और 'सावले' को बदसूरत समझना सावली लूचो वाले लोगों का उपहास करने जैसा था और अंततः कपड़ों के जन्मदा के दबाव के आगे झुकना पड़ा।



हालांकि मेहनतकश अमेरिकी परिवारों और ग्रामीण समुदायों की चुप्पटी को लेकर अमेरिकी की रुचि समझी जा सकती है लेकिन मूडबंदीकरण के तहत हर देश को उन दक्षियों हजारों किसानों की आजीविका की भी रक्षा करनी चाहिए जो दुनिया के किसी और हिस्से में सुरक्षित आयातों के चरते तालब हो जाते हैं। यह न भूलें कि भोजन का आयात करना बेरोजगारी का अयात करने के समान है। मुझे याद है कि मैंने जर्मन किसानों से भी कमीशनें इसी तरह का प्रश्न पूछा था, जो दक्षिणी जर्मनी के लैंडरसफुलर में प्रसंग हारुड में डेनिस के दौरान ज़ूमरुडी नियंत्रकों के एक छोटे समूह से मिलने आए थे (मेरी पुस्तक गेट टू इन्फ्लेट्रीओ को पढ़ना के बीज 95के रूप में पब्लिशर्स, नई दिल्ली)। यह 1990 के दशक के मध्य में किसी समय का वाक्या है। मानता हूँ कि आप सरलस्वत खाल्टन का उत्पादन करते हैं और चावल लिए आप दक्षिण में एक स्पष्ट बाजार की तलाश कर रहे हैं। लेकिन चावल आयातों इस बात का अहसास करने का प्रयास किया जा रहा है। मजदूरों की तीव्र हमेशा से विकारशील देशों के बाजार में पड़च बनाने की तीव्र इच्छा रही है। जिसमें थ्यान का केंद्र स्वामित्विक तौर पर भारत का विशाल बाजार

अगुवाई करते हैं, मुझे वाह किसानों से जो उत्तर मिला, वह अत्यधिक समर्थन प्रदान करने वाला था। भारतीय किसानों के साथ एकजुटता बंध करके हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें इस बात से जकाश नहीं थी कि उनका अधि रोषे खाल्टन भारत में आजीविका को नष्ट कर देगा। जर्मनवासी किसान भारतीय किसानों की पीड़ा को समझ सकते थे और इसलिए चाहे थोड़े कि सुधारवात्मक कदम उठाए जाएं।

मैंने सोचा कि अमेरिका को भी उस तरह का आकाल करना चाहिए जो बादम, अवरोर और सरे समेत अन्य चीजों पर प्रतिरोधात्मक आयात शुरू वापस लेने के बाद भारत पर पड़ेगा। बलो यात्रे सेव की बात करते हैं। सामान्य रियायतों के अनुसार, 20 फ्रीस्ट्री आयात शुरू वृद्धि वापस लेने के बाद जब पहली बच्चे भारत के लिए रवाना हुईं तो सिंपल बंदरगाह पर उत्सव मनाया गया। मैंने सोचा कि अमेरिका के सेव के लिए 120 मिलियन डॉलर का बाजार प्रदान करता है, जिससे अमेरिका में 68,000 सेव उत्पादक किसानों को लाभ होगा। रिपोर्टर के निष्कर्ष, नवंबर 2023 में आयात शुरू आर्थिक रूप से वापस लेने के एक महीने के भीतर 1.95 मिलियन डॉलर मूय के वाशिगटन सेव भारत हो चुके।

जैसा कि सुमरीय है, यूएस कांग्रेस की चुनौती में एक सीट पर को यह कहते हुए पसंदि किया गया कि भारतीय गैर-संसिडी कीमतों को बियाइ रही है और इससे अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। एक अन्य सीटवर ने चावल संसिडी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अगर चावल संसिडी इन्फ्लेट्रीओ को मानवदंडों के भीतर होती, तो इससे अमेरिकी थान किसानों के लिए 860 मिलियन डॉलर के व्यापार के अवरस खुल जाता। यदि आयात आजाज खुल जाते, तो ये सीटवर भारत में एमएसपी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जिसके तहत खासकर पंजाब और हरियाणा में गैर-उत्पन्न चावल उत्पादक किसान, उच्च सुनिश्चित जाहिर से लाभान्वित होते हैं। अमेरिका

ने बार-बार कहा है कि भारत किसानों को उत्पाद-विशेष के लिए समर्थन की 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक एमएसपी भूतानत करके इन्फ्लेट्रीओ की शर्तों का उल्लंघन करता है। आश्चर्यजनक तौर पर, ये अक्षेप बार-बार उस देश द्वारा लगाये जाते हैं जो दुनियाभर के कपास उत्पादकों को हानि पहुंचाने के लिए अपने देश के कपास उत्पादकों को दौं जाने वाली भारी-भरकम संसिडी को बंद करने में विफल रहा हो। उसा तुलना ही करे तो, नई दिल्ली स्थित इन्फ्लेट्रीओ अध्यान केंद्र के अनुसार, अमेरिका अपने 8,100 कपास उत्पादकों को प्रति किसान 117,494 डॉलर की घरेलू मदद प्रदान करता है। इसके विपरीत, 9 मिलियन से अधिक संख्या वाले भारतीय कपास उत्पादकों को प्रति किसान मासुकी 27 डॉलर मिलते हैं। अमेरिका द्वारा अपने किसानों में उपलब्ध पानी के जाने वाली कपास संसिडी के विवादस्पद मुद्दे पश्चिमी अफ्रीका के देशों और भारत में लाइव कृषकों की आजीविका को खत्म करने के लिए जाना जाता है, साल 2003 में असफरत कैननक इन्फ्लेट्रीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के एक प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आने के वक से अनुसूचना बना हुआ है।

मुझे यह भी आजीब लगता है कि जब अमेरिकी सीनेटर उस हालत में भारत के झीगा उद्योग में बात मजदूरी पर सवाल उठाते हैं जब अमेरिकी कृषि क्षेत्र सैकड़ों की तादद में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त करने के लिए जाना जाता है, और कुछ तो 10-12 वर्ष की नाजुक उम्र में जाणिष्किक फार्म में श्रम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, में भी संसार में कहीं भी खेती के काम में लाभश्रम का विशेषी है। लेकिन जब खेती के कार्य में बात श्रमिकों को लगाने की बात आती है, तो अमेरिका में इससे अछूता नहीं। यह निषेध स्थिति नहीं जो स्वतंत्र व्यापार सुनिश्चित करती हो। फ्री ट्रेड का अर्थ अर्थ अर्थ में यह मतलब नहीं कि यह 'फेर और लवली' न-लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।

## गहराता जल-संकट



—ललित गर्ग—

मानवीय गतिविधियों और कृषि-कलाओं के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन साथ मानवीय जीवन के हर पहलू के साथ जानाजोय एवं नदियों के लिए खतरा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख जलधाराओं और नदी घाटियों में कुल जल भंडारण पर खतरनाक स्तर पर महसूस किया जा रहा है, जिससे काफी चिंता पैदा हुई है। वर्तमान में, सिंधी नदी को गंभीर जल परिणाम भ्रान्तों से लगे हैं। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते दरों के बिना संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई वितालानन गिरावट की तथवीं उपकरणों हैं। रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल 2024 तक देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी में 15% गंभीर क्षमता के अनुपात में तीस से भीतर प्रतिशत की गिरावट आई है। जो हास के वर्षों की तुलना में गीने के पानी की उपलब्धता और जलवियुत उत्पादन पर प्रभाव के बारे में वितारें बढ़ रही हैं। महिषों को जल नौनां वर्ष भी बाधित हैं और अधिक गीने पानी की आशंका में बढ़ा जल संकट उपराने बाला है।

लंबे समय तक चरने वाला न होने कारण जल भंडारण में यह कमी है। जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में सूखे हो रहे हैं और अग्ररुक्ति फलाने पैदा हो गई है। जिससे विभिन्न हालातों पर दुर प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि देश की आधी कृषि योग्य भूमि आज भी मानसूनी बारिश के निर्भर है। ऐसे में सामान्य मानसूनी की स्थिति पर कृषि का माधुष्य लंबे तक निर्भर करता है। वास्तव में लगातार बढ़ती गीने का कारण जल संकट में तेजी से गिरावट आई है। इसके गंभीर परिणामों के चलते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। देश का आईटी हब बंगलुरु गंभीर रूप से जल संकट में है। जिसका अरर न केवल कृषि गतिविधियों में बढ़ा है बल्कि रोजगार की जिंदगी भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसी आसान संकट से निपटने के लिए जल संकषण के प्रयास परों से लेकर तामा कृषि पद्धतियों और औद्योगिक कार्यों तक में तेज काम की जरूरत है, जिसके 42 जलाशय वर्तमान में केंवल 17 प्रतिशत क्षमता पर हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई सबसे कम जल क्षमता का प्रतीक है। स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी

वितालानक है, पश्चिम में 34 प्रतिशत और उत्तर में 32.5 प्रतिशत जलाशय क्षमता है। हालांकि, पूर्वी और मध्य भारत की स्थिति बेहतर है, उनके तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन साथ मानवीय जीवन के हर पहलू के साथ जानाजोय एवं नदियों के लिए खतरा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख जलधाराओं और नदी घाटियों में कुल जल भंडारण पर खतरनाक स्तर पर महसूस किया जा रहा है, जिससे काफी चिंता पैदा हुई है। वर्तमान में, सिंधी नदी को गंभीर जल परिणाम भ्रान्तों से लगे हैं। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते दरों के बिना संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई वितालानन गिरावट की तथवीं उपकरणों हैं। रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल 2024 तक देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी में 15% गंभीर क्षमता के अनुपात में तीस से भीतर प्रतिशत की गिरावट आई है। जो हास के वर्षों की तुलना में गीने के पानी की उपलब्धता और जलवियुत उत्पादन पर प्रभाव के बारे में वितारें बढ़ रही हैं। महिषों को जल नौनां वर्ष भी बाधित हैं और अधिक गीने पानी की आशंका में बढ़ा जल संकट उपराने बाला है।

लंबे समय तक चरने वाला न होने कारण जल भंडारण में यह कमी है। जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में सूखे हो रहे हैं और अग्ररुक्ति फलाने पैदा हो गई है। जिससे विभिन्न हालातों पर दुर प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि देश की आधी कृषि योग्य भूमि आज भी मानसूनी बारिश के निर्भर है। ऐसे में सामान्य मानसूनी की स्थिति पर कृषि का माधुष्य लंबे तक निर्भर करता है। वास्तव में लगातार बढ़ती गीने का कारण जल संकट में तेजी से गिरावट आई है। इसके गंभीर परिणामों के चलते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। देश का आईटी हब बंगलुरु गंभीर रूप से जल संकट में है। जिसका अरर न केवल कृषि गतिविधियों में बढ़ा है बल्कि रोजगार की जिंदगी भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसी आसान संकट से निपटने के लिए जल संकषण के प्रयास परों से लेकर तामा कृषि पद्धतियों और औद्योगिक कार्यों तक में तेज काम की जरूरत है, जिसके 42 जलाशय वर्तमान में केंवल 17 प्रतिशत क्षमता पर हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई सबसे कम जल क्षमता का प्रतीक है। स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी







